

लेटलतीफी : जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री ने दो साल में पूरा करने की कही थी बात, अफसरों को शासन के आदेश का इंतजार दावा हुआ फेल... आइआइटी इंदौर का 'उज्जैन सैटेलाइट कैंपस' अब तक अधर में, 474 करोड़ की लागत से बनेगा



पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

इंदौर. आइआइटी इंदौर का उज्जैन में प्रस्तावित सैटेलाइट कैंपस का काम अब तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस परियोजना को लेकर दावा किया था कि एक से दो साल में सैटेलाइट कैंपस तैयार हो जाएगा, लेकिन जून 2025 आ चुका है और काम की शुरुआत तक नहीं हुई है। 474 करोड़ रुपये की लागत से यह

सैटेलाइट कैंपस 100 एकड़ भूमि पर बनेगा। हालांकि, परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और राज्य सरकार ने इसे 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तावित किया था, लेकिन निर्माण कार्य का शून्य स्तर पर होना कई सवाल खड़े करता है। आइआइटी इंदौर के पीआरओ सुनील कुमार ने कहा, राज्य सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस निर्देश नहीं मिला है। जब भी शासन की ओर से निर्देश मिलेगा, हम काम शुरू करने को तैयार हैं।

नई शैक्षणिक सत्र की घोषणा, पर भवन नहीं जानकारी के मुताबिक सैटेलाइट कैंपस को लेकर आइआइटी प्रबंधन ने एक कार्ययोजना बनाकर शासन को भेज दी है और सत्र 2025-26 से शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने की बात कही जा रही है। इसके लिए विक्रम विश्वविद्यालय परिसर के अस्थायी भवन का उपयोग करने की योजना है। लेकिन भवन निर्माण का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

उज्जैन के लिए थी बड़ी उम्मीदें

सैटेलाइट कैंपस में एस्ट्रोनॉमी, वाटर रिसर्च, बिजनेस रिसर्च और डीप टेक जैसे 5 खास विषयों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध कार्य होने थे। कैंपस में लैब-टू-मार्केट सेंटर, रिसर्च एंड इनोवेशन हब और स्पेस टेक्नोलॉजी डिस्कवरी सेंटर जैसे यूनिट्स प्रस्तावित हैं, जिससे युवाओं और वैज्ञानिक शोधकर्ताओं को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।

उठे सवाल... अब तक अधर में क्यों?

आइआइटी इंदौर के सूत्रों का कहना है कि राज्य-केंद्र के बीच धीमी प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण यह महत्वाकांक्षी परियोजना ठप पड़ी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनवरी 2024 में कहा था कि यह परियोजना केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयासों से जल्दी शुरू होगी, लेकिन 17 महीने बीत जाने के बावजूद स्थानीय जमीन पर एक ईंट तक नहीं रखी गई है।